प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

27.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो उसके पिछले एक साल के बिजली के बिल के साथ आकंलन कर कमियों को दूर किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर मानक तय किए है। उन्होनें कहा कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाते है तो केंद्र सरकार पैसे में कटौती करेगी। विधायक राम कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार नियमों में संशोधन करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडू, कर्नाटक और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में इस तरह के संशोधन किए जा चुके हैं। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सत्यानंद स्टोक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलारू में युक्तिकरण करके स्टाफ को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र का भवन बनकर तैयार हो चुका है।

हंगामा

इससे पूर्व प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के दौरान हिमकेयर योजना में 11 सौ करोड़ के घोटाले संबंधी आरोपों को बेबुनियाद व तथ्यों से विपरीत बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 11 सौ करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों पर कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर 4 सौ 41 करोड़ रुपये खर्च हुए, ऐसे में 11 सौ करोड़ रुपये का घोटाला कैसे संभव है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 सौ करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वास्तविक अनियमितता करीब एक सौ 20 करोड़ रुपये की है।

एक्साइज डयूटी

केंद्र सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर एक्साइज डयूटी कम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार अब पैट्रोल पर एक्साइज डयूटी 13 रूपए से घटाकर शून्य कर दी गई है जबकि डीजल पर 10 से घटाकर 3 रूपए प्रति लीटर की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन–एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में निर्मला सीतारामन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक बुलाई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक अन्य निर्णय में जो रिफाइनरियां विदेशों से सामग्री लेकर भारत में परिष्कृत करती हैं और निर्यात के लिए भेजती हैं, उन्हें अब अधिक शुल्क देना होगा।

इंदुबाला

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश में एक हजार 5 सौ 38 किलोमीटर लम्बी दो सौ 94 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सांसद इंदुबाला गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे सवाल के जवाब में

उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए करीब 2 हजार 2 सौ 47 करोड़ 24 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाजार, स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षा संस्थानों और विकास केन्द्रों में आवाजाही सुगम बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सड़कों के अपग्रेडेशन का प्रावधान नहीं किया गया है।

————————————————